क्रमांक	स्वयंसेवी एजेंसी का ब्यौरा	स्वीकृत राशि (रुपये में)	रिलीज राशि (रुपये में)
28.	रूरल डेवेलपमेंट सोसाइटी ग्राम/पोस्ट पानालव, जिला-पंचमहल	2,07,000	1,03,000
29.	सारथी पंचमहल, ग्राम/पोस्ट गोधारा पश्चिम, वाया लूनावारा, जिला-पंचमहल	5,83,000	2,00,000
30.	श्री धोरेला केलवानी मंडल स्थान धारधाला, तालुक-लिमखोडा, जिला-पंचमहल	2,07,000	1,03,000
31.	श्री सरस्वती केलवानी ट्रस्ट जाफराबाद, गोधरा पंचमहल, जिला-पंचमहल	1,58,887	1,58,887
32.	लोक विज्ञान सेवा संघ, ग्राम/पोस्ट ब्यारा, जिला-पंचमहल	4,14,000	2,02,400

Shelter Upgradation under Nehru Rozgar Yojana in Madhya Pradesh

1860. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any central scheme for shelter upgradation under Nehru Rozgar Yojana is being implemented by Government in Madhya Pradesh;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) the number of dwelling units upgraded under the scheme during the last three years, year-wise and district-wise;

(d) whether any target for 1996-97 has been fixed and funds earmarked for the State; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) to (c) Though the Scheme of Housing and Shelter Upgradation (SHASU), one of the Schemes of the Nehru Rozgar Yojana, is being implemented in the country since October, 1989, the Government of Madhya Pradesh has not yet taken up the scheme for implementation.

(d) and (e) The subsidy funds to the tune of Rs. 68.80 lakhs under SHASU have been earmarked for Madhya Pradesh for 1996-97 with a target of 11,467 dwelling units to be upgraded.

मध्य प्रदेश में नेहरू रोजगार योजना का कार्यान्वयन

1861. **श्री अजीत जोगी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में नेहरू रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) योजना के प्रारम्भ में 1989-90 से 1995-96 तक मध्य प्रदेश सरकार को 5332.70 लाख रुपये की केन्द्रीय धनराशि दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए राज्य हेतु 480.00 लाख रुपये का केन्द्रीय नियतन किया गया है।

(ख) केन्द्रीय निधियां जिलों को सीधे ही जारी नहीं की जाती। केन्द्रीय निधियां राज्यों को जारी की जाती हैं फिर राज्य, निधियों को विभिन्न जिलों को देते हैं।

Import of LNG

1862. PROF. NAUNIHAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry of Petroleum has a proposal to import Liquefied Natural Gas;

(b) if so, the quantum of LNG proposed to be imported and the reasons for doing so;

(c) what is the demand of LNG in the country per day;

(d) whether the LNG is now being imported from one or several countries, with names thereof;

(e) the quantum of LNG proposed to be imported on daily basis and the amount involved; and

(f) whether there is a gap between the supply and demand; if so, the manner in which Government are going to bridge this gap?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) Yes, Sir. Government Oil Companies are considering proposal for import of LNG.

(b) and (c) The demand for LNG is being assessed. The quantum to be imported will depend on the assessed demand.

(d) LNG is not being imported at present.

(f) No LNG is being supplied at present. The demand for LNG is being assessed and is proposed to be met through imports.

उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता दिया जाना

1863. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी गई;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-वार और योजना-वार वास्तव में कुल कितनी राशि का आबंटन किया गया;

(ग) प्रत्येक मामले में मांगी गई पूरी सहायता न देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष में मांगी गई अतिरिक्त सहायता दे दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई कुल अतिरिक्त वित्तीय सहायता 460 करोड़ रुपये थी;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-वार और योजना-वार वास्तव में आबंटित राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	स्कीमें
1993-94	—	—
1994-95	1.00	स्वास्थ्य सुधार और ग्रामीण विकास
1995-96	5.00	(i) ऋषीकेश-जोशी-मढ़-बद्रीनाथ-मान रोड का सुधार।
	4.125	(ii) उत्तराखंड में आगजनी की रोकथाम तथा नियन्त्रण।
	10.00	(iii) पहाड़ी जिलों में 20 समूहों के लिए चयनित विकासात्मक गतिविधियां।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित फार्मूला और मानदण्ड के अनुसार राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है। वार्षिक योजना में दिए गए संसाधनों पर परवर्ती अतिरिक्त सहायता स्वीकृत करने से पहले विचार किया जा चुका है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई अतिरिक्त सहायता नहीं मांगी गई है;

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

Electronic Projects under MPLAD Programme

1864. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of